

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(मुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-

64 / 2017

प्रविष्टि दिनांक:-

30.11.2017

विजय कुमार कच्छल पुत्र स्व० श्री शंकर लाल कच्छल जाति अग्रवाल महाजन निवासी
देवली तहसील देवली जिला टोंक राज०

..... अपीलाण्ट

बनाम

- 1-ग्राम पंचायत पनवाड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला टोंक
- 2-ग्राम पंचायत पनवाड जरिये सचिव ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला टोंक
- 3-तहसीलदार देवली जिला टोंक

..... रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 तहसीलदार देवली

उपस्थित: (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलाण्ट

(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2

(3) श्री मजहर आलम, परोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 27.08.2021

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० का आवासीय परिवर्तन का नामान्तरण सिवायचक स्वीकार किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है० भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नहीं है। संपरिवर्तन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष में नहीं है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के बाद रूपान्तरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व भूमि मानकर नहीं किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एवं औद्योगिक परिवर्तन होने के बाद में इस रकबा को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तरण तस्दीक किया जा सकता है। रूपान्तरण के संबंध में राज्य सरकार ने भी परिपत्र द्वारा निर्देशित किया है कि रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम किये जाने के प्रावधान हैं। तथाकथित नामान्तरण के बाद बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भू-धारक राज्य सरकार एवं खातेदार की जगह सिवायचक गैर मुमकिन आबादी एवं गैर मुमकिन औद्योगिक हाजा का अकन भी अनाधिकृत व अवैध है। आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० भूमि में से रकबा 0.10 है० भूमि गैर मुमकिन आबादी में तथा रकबा 0.10 है० भूमि औद्योगिक में चले जाने के कारण से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से कम करने के लिए ही नामान्तरण स्वीकृत किया



1084



जा सकता है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 को स्वीकार किये जाने से अपीलांट व्यथित होकर उक्त नामान्तकरण को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेंटस जरिये सम्मन की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।


विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० का आवासीय परिवर्तन का नामान्तकरण सिवायचक स्वीकार किया गया है, जो आदेश अनाधिकृत है और (शून्य है) आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है० भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नहीं है। संपरिवर्तन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष में नहीं है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण के बाद रूपान्तकरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व भूमि मानकर नहीं किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एवं औद्योगिक परिवर्तन होने के बाद में इस रकबे को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता है। तहसीलदार देवली ने विधि के इस बिन्दू पर विचार न कर अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के ही आदेश दिये हैं। रूपान्तरण के संबंध में राज्य सरकार ने भी परिपत्र द्वारा निर्देशित किया है कि रूपान्तकरण होने के पश्चात भूमि खातेदारी में से कम किये जाने के प्रावधान है। तथाकथित नामान्तकरण के बाद बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भू-धारक राज्य सरकार एवं खातेदार की जगह सिवायचक गैर मुमकिन आबादी एवं गैर मुमकिन औद्योगिक हाजा का अंकन भी अनाधिकृत व अवैध है। आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० भूमि में से रकबा 0.10 है० भूमि गैर मुमकिन आबादी में तथा रकबा 0.10 है० भूमि औद्योगिक में चले जाने के कारण से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से कम करने के लिए ही नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या-एफ 6 (26)राज० 6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अनुसार संपरिवर्तन हेतु प्राप्त होने वाले आवदेन पत्रों का निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक है। परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन आदेश होने के बाद संपरिवर्तन हुई भूमि को खातेदार की खातेदारी की भूमि में से कम कर शेष भूमि का तहसीलदार द्वारा आवश्यक इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। तहसीलदार देवली द्वारा उपरोक्त परिपत्र पर कोई गौर नहीं किया गया है। अवैधानिक रूप से सिवायचक का अंकन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम नामान्तकरण भरवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अभिभाषक रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० वाके ग्राम पनवाड अपीलांट की खातेदारी की भूमि है।



1085


बतिरिस्त विभा फलेस्ट
दोष -

अपीलांट ने उक्त भूमि मे से 0.20 है० भूमि का औधोगिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है। तथाकथित भूमि पर ग्राम पंचायत पनवाड का कोई अधिकार एवं कब्जा नहीं है और ना ही राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत पनवाड को दिया गया है। तत्समय तहसीलदार देवली द्वारा तथाकथित नामान्तकरण किन नियमों के परिपेक्ष्य मे ग्राम पंचायत पनवाड के पक्ष मे दर्ज किया गया है ज्ञात नहीं है। अतः अपीलांट उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार करवाना चाहता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक रेसपो. संख्या 3 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली को विजय कुमार पुत्र शकर लाल महाजन सा.देवली खातेदार के स्थान पर सिवायचक आवासीय गै.मु.आबादी एवं गै०मु० औधोगिक के नाम का नामान्तकरण तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया है। प्रश्नगत नामान्तकरण प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 केम्प दिनांक 27.12.2004 ग्राम पंचायत पनवाड मे तस्दीक/स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण मे अगर किसी प्रकार की ऋट्टि है तो तहसीलदार देवली को पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्याय संगत है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली को विजय कुमार पुत्र शकर लाल महाजन सा.देवली खातेदार के स्थान पर सिवायचक आवासीय गै.मु.आबादी एवं गै०मु० औधोगिक के नाम का नामान्तकरण तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार देवली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2004 से आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.27 है० का आवासीय परिवर्तन का नामान्तकरण सिवायचक स्वीकार किया गया है, जो आदेश अनाधिकृत है और (शून्य है) आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 है० भूमि की खातेदार ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली नहीं है। संपरिवर्तन का आदेश भी ग्राम पंचायत पनवाड अथवा तहसीलदार देवली के पक्ष मे नहीं है। अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण के बाद रूपान्तकरण किया गया रकबा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व भूमि मानकर नहीं किया जा सकता है। गैर मुमकिन आबादी एवं औधोगिक परिवर्तन होने के बाद मे इस रकबे को तो केवल राजस्व रिकार्ड से कम करने के लिए ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा सकता है। तहसीलदार देवली ने विधि के इस बिन्दू पर विचार न कर अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के ही आदेश दिये है।

अभिभाषक रेसपो. संख्या 1 व 2 तर्क है कि तथाकथित भूमि पर ग्राम पंचायत पनवाड का कोई अधिकार एवं कब्जा नहीं है और ना ही राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत पनवाड को दिया गया है। अपीलांट उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार करवाना चाहता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।



1086

बहिसर विभा कन्स्ट.
दोष

अभिभाषक रेसपो. संख्या 3 ने भी तर्क दिया है कि नामान्तकरण मे अगर किसी प्रकार की ऋटि है तो तहसीलदार देवली को पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना न्याय संगत है।

उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि तहसीलदार देवली ने उक्त नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट की सुनवाई नही की है। तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तकरण प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 केम्प दिनांक 27.12.2004 ग्राम पंचायत पनवाड मे तस्दीक/स्वीकार किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने भी अपीलांट की सुनवाई नही करने बाबत अपील मीमो मे आपत्ति की है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 676 दिनांक 27.12.2004 वाके ग्राम पनवाड पर तहसीलदार देवली द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार देवली को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 10.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली के समक्ष समय 10.00 ए. एम.पर उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मसारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)